भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग **लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2009

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया

राजस्थान द्वारा एनपीएस को हटाना

2009. श्री दीपक बैजः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त कर दिया है और 23/02/2022 को एनपीएस के तहत सभी अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापस करने की घोषणा की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केंद्र सरकार भी राजस्थान राज्य सरकार की तर्ज पर एनपीएस को खत्म कर देगी और केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को ओपीएस के तहत वापस लाएगी:
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

- (क) और (ख): राजस्थान राज्य सरकार ने 23 फरवरी, 2022 को बजट भाषण में 1 जनवरी, 2004 को या इसके पश्चात् नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है।
- (ग) से (ड.): ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES *****

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2009 TO BE ANSWERED ON 14th MARCH, 2022 (MONDAY)/ PHALGUNA 23, 1943 (SAKA) SCRAPPING OF NPS BY RAJASTHAN

2009. Shri Deepak Baij:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the State Government of Rajasthan has scrapped New Pension Scheme(NPS) and has announced to revert all officials under NPS to Old Pension Scheme(OPS) on 23/02/2022;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether the Union Government would also scrap NPS and revert all officials of Central Government under OPS on the line of State Government of Rajasthan;
- (d) if so, the details thereof; and
- (e) if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD)

- (a) and (b) State Government of Rajasthan in Budget Speech on 23rd February, 2022, announced to implement old pension scheme from the forthcoming year, for all employees appointed on or after 1st January, 2004
- (c) to (e) There is no proposal under consideration of Government of India.
